

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकितप्रश्नसं. *69
शुक्रवार, 23जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूकंप संबंधी वेधशालाओं की स्थापना

*69. श्री रामचरण बोहरा:

क्या पृथ्वी विज्ञानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भूकंपों का अध्ययन करने के लिए देशभर में भूकंप संबंधी वेधशालाओं की स्थापना करने हेतु कोई नीति बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) ये वेधशालाएं कब तक कार्य आरंभ कर देंगी?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रखा है।

“भूकंप संबंधी वेधशालाओंकी स्थापना”के बारे में लोकसभा में शुक्रवार 23 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *69 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(1) जी, हां।

(2) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र देश में तथा इसके आस-पास भूकंपोंकीनिगरानी तथा अध्ययन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेन्सी है। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्रके पास एक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान संबंधी नेटवर्क है जिसमें देश भर में फैली 115 वेधशालाएं शामिल हैं। यह नेटवर्क दिल्ली में तथा इसके आसपास 2.5 या इससे अधिक तीव्रता वाली, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3.0 या इससे अधिक तीव्रता वाली, प्रायद्वीपीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में 3.5 या इससे अधिक तीव्रता वाली, अंडमान क्षेत्र में 4.0 या इससे अधिक तीव्रता वाली तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में 4.5 या इससे अधिक तीव्रता वाली किसी भी घटनाको रिकॉर्ड करने में समर्थ है। कमी वाले क्षेत्रों में स्थानिक रूप से सुधार करने तथा देश में भूकंप की तीव्रता की पहचान सीमा को 3.0 तक लाने के लिए, देश में 35 नए केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है तथा इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। देशभर में 2.5 तीव्रता तक भूकंप की पहचान क्षमता को बढ़ाने के लिए आगामी 5 वर्षों में 100 भूकंप केन्द्र स्थापित कर राष्ट्रीय भूकंप संबंधी नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने की भी योजना है।

(3) सभी 35 नए केन्द्र दिसंबर, 2021 तक स्थापित कर दिए जाएंगे तथा कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार, दिसंबर, 2021 तक राष्ट्रीय भूकंप संबंधी नेटवर्क में 150 केन्द्र हो जाएंगे। बाद में, मार्च, 2026 तक 100 अतिरिक्त नए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

